

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
संख्या: — /VII-II/378-उद्योग/2007
देहरादून : दिनांक 24 फरवरी, 2009

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 11/औद्योग/07-उद्योग/2004 तथा शासनादेश संख्या: 940-उद्योग/औद्योग/07-उद्योग/2004-05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थान अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति-निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्र संख्या: 2000/उद्योग(बैच)-नि0औद्योग/2008-09 दिनांक 8 अगस्त, 2008 के सन्दर्भ में नै0 जे0एन0जे0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 को जिला हरिद्वार, तहसील रुड़की, ग्राम शिकारपुर में 3.9878 हेक्टेअर अतिरिक्त कय अनुबन्धित भूमि जिसके खसरा नम्बर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन श्री राजापाल महोदय निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में विनिर्दिष्ट/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर/रकबा	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)
ग्राम-शिकारपुर तहसील-रुड़की	560 से 566, 570, 573, 574, 591, 591/2	3.9878

2- उक्त तालिका में उल्लिखित खसरा संख्या भारत सरकार, पित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 50/2003-के0उ0शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला हरिद्वार के अन्तर्गत Category-D Expansion of Existing Estate के रूप में क्रमांक-5 पर ग्राम-शिकारपुर, तहसील रुड़की के अन्तर्गत अधिसूचित है। उक्त पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों (नकारात्मक सूची के उद्योगों को छोड़कर) को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ प्राप्तता पूर्ण करने पर अनुमत्य होगा।

3- GIDCR-2005 के पृष्ठ संख्या-34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4- औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-4815/सत्त-2/378-उद्योग/2007 दिनांक 22.1.2008 तथा शासनादेश संख्या: 1539/सत्त-2/378-उद्योग/2007 दिनांक 23.4.2008 में दी गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन करना होगा।

5- इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रकांक कम्पनी द्वारा कय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियन्त्रित भूमि कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान तथा आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

6- औद्योगिक आस्थान के रख-रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। अर्बटी इकाईयों को आर्बटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के संबंध में स्पष्ट सभी सूचनाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी।

7- आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकताएँ अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

8- सभी आवंटियों से यह अप्रैडरटेकिंग ती जायेगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की (Sale Deed)/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

9- निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों तथा प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

10- प्रवर्तक कम्पनी द्वारा आस्थान में भूखण्डों की निर्धारित की गई दरें, विषणन तथा विकास आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड को समय-समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

11- उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उत्सर्धन करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से जिससे शासन सफित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी०सी०शर्मा)
प्रमुख सचिव

पुष्टांकन संख्या 2983 (1)/VII-II-378-उद्योग/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, भा० मुख्यामत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, पामिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, रागस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रुडकी (हरिद्वार)।
14. नो० जे०एम०जे० इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०, ग्राम शिकारपुर, तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार।

✓ 15- NIC Uttarakhand : सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वेबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(पी०सी०शर्मा)
प्रमुख सचिव।